



आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ता नया भारत



₹38,400 करोड़ के रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट से बढ़ा भारत का गौरव
5,500+ रक्षा उपकरण आयात सूची से बाहर,
स्वदेशी रक्षा उत्पादों को बढ़ावा

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के



स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उपयोग और उनके ऐतिहासिक निर्यात के कारण भारत आज पूरे विश्व में नई पहचान और प्रतिष्ठा के साथ उभर रहा है। - श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

डिजिटल तकनीक से सुरक्षित होंगे हाईवे, ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए शुरु हुआ नया अभियान

नई दिल्ली। देश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा और तकनीक आधारित कदम उठाया है। अब तक सड़क सुरक्षा के लिए जिन पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता थी, उनकी जगह अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक लेने जा रही है। सरकार ने हाईवे पर मौजूद खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुधार के लिए डिजिटल ट्विन, थ्री-डी मॉडलिंग, लेजर स्कैनिंग और क्लैश सिमुलेशन जैसी आधुनिक प्रणालियों को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं के कारण बनने वाले तकनीकी दोषों को वैज्ञानिक तरीके से पहचानकर उन्हें स्थायी रूप से दूर करना है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार अब ब्लैक स्पॉट्स की जांच केवल मानव अवलोकन या पारंपरिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेगी। इसके बजाय कंप्यूटर आधारित विश्लेषण और मटेरियल साइंस की सहायता से सड़कों की बारीकियों का अध्ययन किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव देश की सड़क सुरक्षा व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत साबित हो सकता है।

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ने अपनी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में बताया है कि देश के 50 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स का डिजिटल तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण और सुधार किया



जा चुका है। इन स्थानों पर वर्षों से दुर्घटनाएं होती रही थीं और पारंपरिक उपायों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे। अब अत्याधुनिक तकनीक के जरिए सड़क की वास्तविक स्थिति का त्रि-आयामी मॉडल तैयार कर उसकी कमियों को दूर किया गया है।

इस नई प्रणाली के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण वाहनों का उपयोग किया जाता है। इन वाहनों में अत्याधुनिक लिडार सेंसर और 360 डिग्री कैमरे लगाए जाते हैं। जब ये वाहन किसी ब्लैक स्पॉट या दुर्घटना संभावित क्षेत्र से गुजरते हैं, तो लिडार सेंसर प्रति सेकंड लाखों लेजर किरणें सड़क और उसके आसपास के वातावरण पर छोड़ते हैं। ये किरणें सड़क की सतह, डिवाइडर, मोड़, पुल, पेड़, बिजली के खंभे और अन्य संरचनाओं से टकराकर वापस लौटती हैं। इसके बाद कंप्यूटर इन सभी सूचनाओं को जोड़कर उस पूरे क्षेत्र का सटीक त्रि-आयामी डिजिटल मॉडल तैयार करता है।

इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इंजीनियरों को अब हर बार दुर्घटनास्थल

पर जाकर लंबे समय तक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी। एयर-कंडीशन लैब में बैठे विशेषज्ञ कंप्यूटर स्क्रीन पर तैयार किए गए डिजिटल मॉडल का विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और परिणाम भी अधिक सटीक मिलते हैं। डिजिटल मॉडल तैयार होने के बाद उस पर क्लैश सिमुलेशन किया जाता है। यह प्रक्रिया सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें कंप्यूटर पर बनाई गई वर्चुअल सड़क पर विभिन्न गति से डिजिटल वाहन चलाए जाते हैं। 80, 100 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ाकर यह देखा जाता है कि किस स्थान पर वाहन नियंत्रण खो सकता है, किस मोड़ पर पलटने की संभावना अधिक है या किस ढाल पर दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इस परीक्षण के दौरान इंजीनियरों को उन बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है जहां सड़क की संरचना में बदलाव आवश्यक है। विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक निरीक्षण में कई बार सड़क की वास्तविक

तकनीकी खामियां सामने नहीं आ पाती थीं। उदाहरण के लिए किसी मोड़ का कोण कुछ डिग्री अधिक या कम होना, सड़क की ढाल में सूक्ष्म वृद्धि होना अथवा दृश्यता का सीमित होना जैसी समस्याएं सामान्य निरीक्षण में नजर नहीं आती थीं। लेकिन डिजिटल ट्विन तकनीक इन सभी पहलुओं का अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण कर सकती है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अनुसार 100 सबसे संवेदनशील ब्लैक स्पॉट्स के लिए शुरु किए गए पहले चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब दूसरे चरण में शेष स्थानों की डिजिटल मैपिंग और सुरक्षा सुधार कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य है कि वर्ष 2026 के अंत तक देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद अधिकांश खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित बनाया जा सके।

इस अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मार्गों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर कॉरिडोर, वाराणसी-औरंगाबाद-बरेली मार्ग के पहाड़ी मोड़, मुजफ्फरपुर-बरेली खंड के व्यस्त जंक्शन, ऋषिकेश-धरमपुर मार्ग तथा टनकपुर-पिथौरागढ़ के संकरे और तीव्र ढाल वाले हिस्से प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और यातायात के दबाव के कारण दुर्घटनाओं की संभावना अपेक्षाकृत अधिक रहती है।

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल ट्विन तकनीक केवल ब्लैक स्पॉट

सुधार तक सीमित नहीं रहेगी। भविष्य में इसका उपयोग नए हाईवे डिजाइन करने, पुलों की सुरक्षा जांच करने और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इससे सड़क निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी।

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफी अधिक है। हर वर्ष लाखों लोग सड़क हादसों में घायल होते हैं और हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में तकनीक आधारित यह पहल केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि यह मॉडल सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से अधिक सुरक्षित, आधुनिक और दुर्घटनारहित बन सकते हैं।

सरकार का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों के पालन से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि सड़क की इंजीनियरिंग गुणवत्ता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि अब दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए डिजिटल विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में सड़क हादसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी और देश के हाईवे वास्तव में ब्लैक स्पॉट मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

जी-7 शिखर सम्मेलन में दिखी भारत-अमेरिका की नजदीकी, 16 महीने बाद आमने-सामने आए मोदी और ट्रम्प

एवियन/नई दिल्ली। फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया की दो प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियों भारत और अमेरिका के नेताओं की मुलाकात वैश्विक कूटनीति का प्रमुख आकर्षण बन गई। प्रधानमंत्री Narendra Modi और अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump करीब 16 महीने बाद आमने-सामने आए। दोनों नेताओं के बीच हुई संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण बातचीत ने एक बार फिर भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर अंतरराष्ट्रीय हलकों में चर्चा तेज कर दी है। जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के दौरान दोनों नेता एक-दूसरे के साथ बैठे नजर आए। बैठक के दौरान दोनों के बीच लगभग पांच मिनट तक बातचीत हुई। यद्यपि यह औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं थी, लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और चर्चा की, उसने दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत हो रहे संबंधों की झलक पेश की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प की इससे पहले आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में हुई थी। उसके बाद पहली बार दोनों नेता किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर आमने-सामने आए हैं। ऐसे समय में यह मुलाकात विशेष महत्व रखती है, जब वैश्विक व्यापार, रणनीतिक सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।

जी-7 सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की बीच व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की संभावना भी बताई जा रही है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश, आपूर्ति

शृंखला, उन्नत तकनीक और रणनीतिक सहयोग से जुड़े विषयों पर बातचीत हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की दिशा में यह चर्चा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे अनेक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। ऐसे में मोदी और ट्रम्प की यह मुलाकात केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी के संकेत के रूप में भी देखी जा रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर पहले से चर्चा चल रही है।

जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति भी विशेष महत्व रखती है। भारत जी-7 समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक महत्व को देखते हुए उसे लगातार आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। इस वर्ष का सम्मेलन भारत की 13वीं भागीदारी को चिह्नित करता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सातवीं बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच में हिस्सा ले रहे हैं, जो विश्व राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत माना जा रहा है।

एवियन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron ने किया। सम्मेलन के दौरान आयोजित समूह फोटो सत्र में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक साथ दिखाई दिए। यह तस्वीर वैश्विक सहयोग और बहुपक्षीय कूटनीति का प्रतीक मानी जा रही है।

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई अन्य प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात और बातचीत की। इनमें जर्मनी के चांसलर Friedrich Merz, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer, कनाडा के प्रधानमंत्री Mark Carney तथा इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni प्रमुख रूप से शामिल रहे। इन नेताओं के साथ हुई बातचीत में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक चुनौतियों जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होने की संभावना बताई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में भारत विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में उसकी बढ़ती भूमिका, तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक महत्व के कारण दुनिया के बड़े देश भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जी-7 जैसे मंचों पर भारत की मौजूदगी लगातार अधिक प्रभावशाली होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को भारत की सक्रिय वैश्विक कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भूमिका को मजबूत किया है और वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाया है। जी-7 सम्मेलन में भागीदारी भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं और प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के साथ सीधे संवाद का अवसर प्रदान करती है। मोदी और ट्रम्प की मुलाकात ने जहां अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, वहीं संभावित व्यापार वार्ता और रणनीतिक सहयोग को लेकर भी नई उम्मीदें पैदा की हैं।

ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम: 200 रुपये में बिकता बचपन, 11 घंटे की मजदूरी में कैद थे मासूम सपने

गांधीनगर। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें, कॉपीयां और रंग-विरंगे सपने होने चाहिए, उस उम्र में कई मासूम मजबूरी, गरीबी और शोषण के अंधेरे जाल में फंसकर कारखानों की मशीनों और मजदूरी की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं। गुजरात में हाल ही में सामने आया एक मामला न केवल बाल श्रम की भयावह तस्वीर पेश करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आधुनिक भारत में आज भी हजारों बच्चों का बचपन बाजार की वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जा रहा है। राज्य पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम' ने ऐसे ही कई दर्दनाक सच उजागर किए हैं, जिनमें मासूम बच्चों को बेहद कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

गुजरात पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी की और पहले ही चरण में 84 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। इन बच्चों को अलग-अलग फैक्ट्रियों, वर्कशॉपों और छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करते हुए पाया गया। अभियान के दौरान सामने आए तथ्य इतने चौंकाने वाले थे कि उन्होंने प्रशासनिक तंत्र के साथ-साथ समाज को भी झकझोर कर रख दिया।

अभियान की निगरानी राज्य के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी कर रहे हैं और इसे गुजरात पुलिस, सीआईडी ब्रिगाड, श्रम विभाग तथा बाल संरक्षण इकाइयों के संयुक्त प्रयास के रूप में संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार केवल 14 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई में 26 ठेकेदारों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 16 आपराधिक मामले दर्ज किए



गए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह केवल बाल श्रम का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जो गरीब परिवारों के बच्चों को रोजगार का झांसा देकर विभिन्न राज्यों से लाकर फैक्ट्रियों में काम पर लगाता है।

इस अभियान के दौरान सबसे गंभीर मामला सूरत की एक कपड़ा फैक्ट्री में सामने आया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां नाबालिग बच्चों से अवैध रूप से काम कराया जा रहा है। सूचना के आधार पर जब अधिकारियों ने जय अंबे टेक्सटाइल्स नामक इकाई पर छापा मारा तो वहां से दो नाबालिग लड़कों को मुक्त कराया गया। पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसने बाल श्रम की क्रूर वास्तविकता को उजागर कर दिया।

पुलिस बच्चों में पता चला कि इन बच्चों से प्रतिदिन लगभग 11 घंटे तक लगातार काम कराया जाता था। सुबह आठ बजे

से लेकर शाम सात बजे तक वे मशीनों और उत्पादन कार्यों में लगे रहते थे। पूरे दिन में उन्हें केवल एक घंटे का भोजन अवकाश दिया जाता था। इसके बदले उन्हें मात्र 200 रुपये प्रतिदिन दिए जाते थे। यह राशि न केवल श्रम कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह उस अमानवीय व्यवस्था की भी तस्वीर पेश करती है, जहां बच्चों के भविष्य की कीमत कुछ सौ रुपये तय कर दी जाती है।

अधिकारियों के अनुसार बच्चों को केवल आर्थिक शोषण का ही सामना नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि मानसिक दबाव और भय का वातावरण भी बनाया गया था। यदि कोई बच्चा थकान या बीमारी के कारण काम करने से मना करता, तो उसे डांट-फटकार, धमकी और दबाव के माध्यम से दोबारा काम पर लगा दिया जाता था। कई बच्चों ने बताया कि उन्हें लगातार यह एहसास कराया जाता था कि यदि वे काम छोड़ देंगे तो उन्हें घर नहीं जाने दिया जाएगा या उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री संचालक और संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

गुजरात के पुलिस महानिदेशक जी.एस. मलिक ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल बच्चों को कारखानों से निकालना नहीं है। वास्तविक चुनौती उन्हें दोबारा शिक्षा और सामान्य जीवन की

मुख्यधारा से जोड़ने की है। उन्होंने बताया कि अब तक रेस्क्यू किए गए 84 बच्चों में से 67 का पुनर्वास किया जा चुका है। उन्हें बाल कल्याण समितियों, आश्रय गृहों और सामाजिक संगठनों की मदद से शिक्षा एवं संरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बाल श्रम केवल कानून और अपराध का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गरीबी, अशिक्षा और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण कई परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मानव तस्करी और श्रमिक आपूर्ति से जुड़े गिरोह सक्रिय हो जाते हैं।

सीआईडी ब्रिगाड के अतिरिक्त महानिदेशक अजय चौधरी के अनुसार रेस्क्यू किए गए अधिकांश बच्चे बिहार और राजस्थान के प्रवासी परिवारों से जुड़े पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि बच्चों को एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से गुजरात लाया गया था। कई मामलों में ठेकेदार गांवों में जाकर गरीब परिवारों को बेहतर रोजगार और कमाई का झांसा देते थे। इसके बाद बच्चों को शहरों में भेजकर विभिन्न उद्योगों में काम पर लगा दिया जाता था। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह केवल स्थानीय स्तर का मामला नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी और श्रमिक आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ा बड़ा रैकेट हो सकता है। इसी कारण जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। बाल श्रम के खिलाफ समाज को जागरूक बनाने के लिए भी राज्य सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है।



गरवी गुजरात हिन्दी



JioTV CHENNAL NO. 2002



Jio Air Fiber



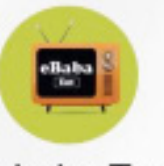
Jio tv+



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

संपादकीय

डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ

भारत में सामान्यतः उत्पादों पर गुणवत्ता व उपयोग-नि्तिथि के दावों के बावजूद उसके सेहत से जुड़े सरोकार सवालों के घेरे में रहे हैं। यह आम धारणा बनी हुई है कि कुछ लोग मुनाफे के लिए सामान की एक्सपाइरी डेट दर्ज करने में हेरफेर करने तक से नहीं चुकते। यह भी विश्वास से नहीं कहा जा सकता है कि सामान में शामिल घटकों का विवरण ईमानदारी से लेबल पर दर्ज किया गया हो। गाहे-बगाहे मीडिया व उम्भोक्ता अदालतों में ऐसे मामलों की गुंज रहती है। स्फा कम्पी-कभार नोटिस से संवेदनशील लोगों के जीवन पर सही लेबलिंग से आंच नहीं आ सकती। इसी के मद्देनजर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा कई खाद्य कंपनियों को गुमराह करने वाले ट्रेड नाम के इस्तेमाल और सेहत से जुड़े दावों के लिए नोटिस जारी करना, निश्चय ही एक स्वागतयोग्य कदम है। अक्सर प्रतिष्ठित उत्पाद वाली कंपनियों के लेबल लगाकर हल्के सामान बेचने के मामले भी उभराए होते हैं। हकीकत है कि आकर्षक पैकेजिंग के जरिये उत्पाद की न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी को पारसर्व में डाल दिया जाता है। विडंबना यह है कि देश में ऐसा नियामक तंत्र विकसित नहीं हो पाया है जो लगातार जनहित में खाद्य उत्पादों की जांच-पड़ताल कर सके। निश्चित रूप से रेगुलेटरी संस्था की निगरानी स्फा कम्पी-कभार नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई कुछ समय के लिए तो सुखियां बनती हैं लेकिन फिर लोगों को इसकी यादों का जवाब ही रह जाती है। इस तरह की पहल को ग्राहकों की सुरक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और जागरूकता पर आधारित लगातार चलने वाले एक राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया जा सकता है। निश्चित रूप से लाखों भारतीयों के लिए खाने की चीजों पर लेबलिंग सेहत से जुड़ा मामला है। मसलन कशेरुक रोग से पीड़ित लोग मल्टिन से बचने के लिए लेबलिंग पर लिखी जानकारी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह उनकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। निस्संदेह, कई एलर्जी व रोगों से जूझने वाले लोगों को कुछ उत्पादों में मौजूद पदार्थों की वजह से लंबे समय तक रहने वाली परेशनियां हो सकती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि उत्पादों के लेबल पर आधी-अधूरी, अस्पष्ट जानकारी ही दी जाती है। अक्सर उत्पादों पर हेलदी, नेचुरल और आयुर्वेद पद्धति पर आधारित जैसे लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करके ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है, जिससे उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में पड़ आते हैं। मधुमेह, एलर्जी और खानपान से जुड़े दूसरे रहरजों में अस्पष्ट व गलत जानकारी हानिकारक हो सकती है। उत्पादकों की ईमानदारी व उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर भरोसा करना ग्राहकों के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे-जैसे भारतीय समाज में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, देश में एक मजबूत नियामक ढांचे की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। दरअसल, देखने में आता है कि छोटे दुकानदार अपने नुकसान को बचाने के लिए उसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं। एक प्रतिबद्ध नैतिकता का अभाव इस मुनाफे के कारोबार में अक्सर नजर आता है। निस्संदेह, किसी उत्पाद के पैकेट में उल्लेखित जानकारी ग्राहक के समझने के लिए आसान होनी चाहिए। साथ ही बिना तथ्य व तार्किकता के सेहत से जुड़े दावे करने वाले उत्पादकों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। इसके लिये जरूरी है कि समय-समय पर इन उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया की औचक निगरानी व पड़ताल होनी चाहिए। साथ ही बार-बार नियम तोड़ने पर कड़े जुमाने का प्रावधान भी होना जरूरी है। देश में कोशिश हो कि उपभोक्ता जागरूकता अभियान को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया जाए। इस अभियान में स्कूलों, हेल्थकेयर संस्थानों और लिथिन मीडिया समूहों को आम लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए कि किसी उत्पाद में दर्ज न्यूट्रिशन लेबल को कैसे समझें। कैसे भ्रमित करने वाले दावों की पड़ताल करें। साथ ही कैसे वे सेहत के अनुकूल उत्पादों के विकल्प का चयन कर सकें। निश्चित रूप से एक जागरूक उपभोक्ता ही अनैतिक मार्केटिंग के खिलाफ बचाव की राह दिखा सकता है। खाद्य उत्पाद से जुड़े कारोबारियों को बचने के बजाय नैतिक दायित्वों के निर्वहन से कारोबार में शुचिता को बनाये रखनी चाहिए।

अभियान

जहां आज भी सुनाई देती है ‘राम-राम’ की ध्वनि, बाबा नीम करौली और हनुमान कृपा का दिव्य धाम कैंची

हिमालय की पवित्र वादियों में कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां पहुंचते ही मन स्वतः शांत हो जाता है, विचार निमल होने लगते हैं और हृदय में भक्ति का एक अनेछा भाव जाग उठता है। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित कैंची धाम ऐसा ही एक अलौकिक तीर्थ है। यह केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभवों का जीवंत स्रोत है। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करता है। कोई मन की शांति पाते आता है, कोई जीवन की समस्याओं से मुक्ति की कामना लेकर आता है, तो कोई केवल बाबा नीम करौली के चरणों में बैठकर उनके दिव्य सान्निध्य का अनुभव करते आता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ कैंची धाम पहुंचता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। देवभूमि उत्तराखंड की हरी-परी पहाड़ियों के मध्य बसा यह पवन धाम प्रकृतिगत सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। चारों ओर देवदार और चीड़ के वृक्ष, बीच से बहती निर्मल धारा, पत्थरी की गेद में फँसी शांत और वातावरण में गुंजाता ‘राम-राम’ का मंत्र यहां आने वाले हर श्रद्धालु को ईश्वर के निकट होने का अनुभव कराता है। यही कारण है कि लोग यहां नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों से लगे लंबे दूरान के लिए पहुंचते हैं। कैंची धाम का नाम भी अपने आप में अत्यंत रोचक

हालांकि, एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके मार्फत ‘नागरिकता की सीमित जांच’ का आधार बना सकता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से एक वर्ग के मन में संशय हैं। खबरें हैं कि बिहार और बंगाल की नई सरकारों ने घोषणा की है कि मतदाता सूची से जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे।

हालांकि, एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके मार्फत ‘नागरिकता की सीमित जांच’ का आधार बना सकता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से एक वर्ग के मन में संशय हैं। खबरें हैं कि बिहार और बंगाल की नई सरकारों ने घोषणा की है कि मतदाता सूची से जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे।

प्रेरणा

संजीवनी की खोज, कालनेमि का छल और तपोवन की अमर कथा

हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम नहीं है, बल्कि वह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म का जीवंत इतिहास भी है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों, दुर्गम घाटियों और रहस्यमयी स्थलों में आज भी ऐसी अनेक कथाएं सांस लेती हैं, जिनका संबंध सीधे रामायणकाल से जोड़ा जाता है। इन्हीं पौराणिक स्थलों में चमोली जनपद की नीति घाटी में स्थित तपोवन का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। लोक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और प्राचीन आख्यानो के अनुसार यहीं वह भूमि है जहां संजीवनी वृदी की खोज में निकले पवनपुत्र हनुमान का सामना रावण द्वारा भेजे गए मायावी राक्षस कालनेमि से हुआ था। यह कथा केवल एक युद्ध प्रसंग नहीं, बल्कि भक्ति, कर्म, तप, तो उसका सप्ताम्य और अहंकार दोनों नष्ट हो जाएँ। इसी उद्देश्य से उसके पुत्र मेघनाथ ने युद्धभूमि में एक अत्यंत शक्तिशाली अस्र का प्रयोग किया। शक्ति बना लक्ष्मण को लगा और वे तत्काल मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि समस्त वनार सेना के साथ स्वयं श्रीराम भी व्रित्तित हो उठे। लक्ष्मण की मूर्छा केवल एक योद्धा के घायल होने की घटना नहीं थी। वह राम के हृदय पर पड़ा ऐसा आघात था जिसने पूरे युद्ध का भविष्य संकट में डाल दिया

था। तब लंका में उपरिष्ठत विख्यात वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण का परीक्षण किया और गंभीर स्वर में कहा कि हिमालय स्थित द्रोणागिरी पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी वृदी ही उनके प्राणों की रक्षा कर सकती है। लेकिन यह औषधि सूर्योदय से पहले लानी होगी, अन्यथा स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाएगी। यह सुनकर सभी व्रित्तित हो गए। हिमालय की दूरी, समय की कमी और औषधि की पहचान जैसी कठिनाइयां सामने थीं। ऐसे समय में केवल एक ही नाम सबके मन में आया—पवनपुत्र हनुमान। श्रीराम ने उन्हें आदेश दिया और हनुमान बिना एक क्षण गंवाए आकाश मार्ग से हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि मानो स्वयं वायु उनके साथ दौड़ रहा हो। इन्हीं घण्टाओं में वह समाचार मिल चुका था। वह जानता था कि यदि हनुमान संजीवनी लेकर लौट आए, तो लक्ष्मण पुनः युद्धभूमि में खड़े हो जाएँ और उसकी पराजय निश्चित हो जाएगी। उसने तुरंत अपने विश्वस्त राक्षस कालनेमि को बुलाया। कालनेमि कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह मायावी शक्तियों में निपुण था और छल-कपट की कला में दक्ष माना जाता था। रावण ने उसे आदेश दिया कि किसी भी प्रकार हनुमान के मार्ग में बाधा डाले और उन्हें संजीवनी तक पहुंचने से रोके। कालनेमि समझ गया कि यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है। उसने रावण को समझाते का प्रयास किया कि जितने वानर ने अनेक लंका में प्रवेश कर उसे हिला दिया, उसके सामने टिक पाना असंभव है। लेकिन रावण के क्रोध के आगे उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं था। अंततः उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गया। कहा जाता है कि तपोवन पहुंचकर



न्यायाधिकरण इस काम को पूरा नहीं कर पाए। यह काम चुनाव परिणाम आने के बाद भी चल ही रहा है। इन 27 लाख में 60 प्रतिशत से ज्यादा वोटर्स की सूची में वापसी हो चुकी है और अंतिम समाचार मिलने तक न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया जारी है। सवाल है कि उनकी सुनवाई के लिए नागरिक-प्रशासन पर राज्य सरकार ने भरोसा क्यों नहीं किया? चुनाव-आयोग की व्यवस्था है कि ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ के कारण कोई नाम ‘अनमैचड’ रह जाए, तो एक सूची में वर्णित दस्तावेजों में से कोई एक देकर अपने नाम को बनाए रखा जा सकता है। पर बंगाल में अविश्वास इतना गहरा था कि उस रास्ते पर जाने के बजाय लंबे रास्ते को अपनाया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए।

कई तरह के सवाल सभी पक्षों से हैं। आयोग ने सूची से गहन-संशोधन के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया? 2002 और 2003 की मतदाता सूचियों तक पहुंच पाना आसान काम नहीं है। पुरानी सूचियां जिस तरीके से बनाई गई हैं, उनमें नाम, पते और वोटर कार्ड

की संख्या खोजना खासा मुश्किल काम है। सामान्य नागरिक कागज-पत्रों के आदी नहीं हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है। देश की आम जनता दस्तावेजों की अभ्यस्त नहीं है। ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ को दूर करने के लिए दस्तावेजों को भी आसान बनाने की जरूरत है। वोटर को पुरानी सूची में अपना नाम खोजने में दिक्कत होती है। उसकी मदद की जानी चाहिए। आयोग की वेबसाइट को सरल बनाने और इस काम को करने वाले बीएलओ को बेहतर तरीके से तैयार करने की जरूरत है भी।

विरोधी-दलों ने इसे ‘वोट चोर’ साबित करते हुए, राजनीतिक सवाल बनाया। चुनाव-आयोग, उसकी प्रक्रिया और ईवीएम की साख पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बात को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। जब उन्हें विजय मिलती है, तब वे सवाल करते, क्यों नहीं करते? दिसंबर में लोकसभा में चुनाव-सुधारों पर हो रही बहस के दौरान एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुई ने कहा, ‘मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं कालनेमि नामक राक्षस है और उसका उद्देश्य उन्हें धोखा देकर उनके कार्य में विलंब करना है। वह सुनते ही हनुमान सब समझ गए। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बनाई और वापस आश्रम की ओर लौटे। आश्रम में पहुंचकर हनुमान ने मुसुकुपते हुए कहा, ‘गुरुदेव, द्वाआ देने से पहले गुरुदक्षिणा स्वीकार कीजिए।’ कालनेमि कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हनुमान ने अपनी पूंछ से उसे जकड़ लिया। अगले ही पल उन्होंने उसे आकाश में घुमाकर इतनी शक्ति से भूमि पर पटका कि उसका मायावी रूप समाप्त हो गया। उसका वास्तविक राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कथा कहती है कि धनुष के अंतिम क्षणों में कालनेमि का अहंकार समाप्त हो गया। उसे समझ आ गया कि धर्म के विरुद्ध खड़े होकर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसने भगवान राम का स्मरण किया और उनके नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार तपोवन की पवित्र भूमि पर एक बार फिर धर्म की विजय और अधर्म की पराजय हुई। इसके बाद हनुमान बिना विलंब किए द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने संजीवनी वृदी खोजने का प्रयास किया, लेकिन असंख्य औषधियों के बीच उसे पहचान नहीं सके। समय तेजी से निकल रहा था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि पूरे पर्वत को ही उठा लिया जाए। अर्धों अद्भुत शक्ति से उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का एक भाग उखाड़ लिया और उसे लेकर लंका की ओर उड़ चले। संजीवनी वृदी के प्रभाव से लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हुए और राम की सेना को नई ऊर्जा प्राप्त हुई।

भारत तक सीमित नहीं रहें। दुनिया की अनेक प्रसिद्ध हरियाणों की उनकी भक्त बर्बाीं। तत्कनीकी जगत के महान उद्यमी Steve Jobs ने अपने जीवन के कठिन दौर में भारत आकर बाबा के आश्रम की यात्रा की थी। बाद में Mark Zuckerberg ने भी स्वीकार किया कि उन्हें भारत में इस धाम के बारे में विशेष जानकारी मिली थी। हॉलीवुड अभिनेत्री Julia Roberts भी बाबा नीम करौली की शिक्षाओं से प्रभावित रही हैं। इन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की यात्राओं ने कैंची धाम को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निाई। प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक Ram Dass का जीवन भी बाबा की कृपा से पूरी तरह बदल गया था। बाबा ने उन्हें ‘रामदास’ नाम दिया था। बाद में उन्होंने बाबा के जीवन और स्वप्नकारों पर आधारित पुस्तकें लिखीं, जिनके माध्यम से पश्चिमी देशों में भी बाबा की ख्याति फैली। उनकी रचनाओं ने लाखों लोगों को भारतीय अध्यात्म और भक्ति परंपरा से जोड़ने का कार्य किया। बाबा नीम करौली सदैव एक साधारण कंबल ओढ़े रहते थे। वह कंबल उनके सदारीपूर्ण जीवन और वैराग्य का प्रतीक बन गया। आज भी श्रद्धालु बाबा को श्रद्धांजलि स्वरूप कंबल अर्पित करते हैं। उनका विश्वास है कि जिस प्रकार बाबा ने अपने जीवन में असंख्य लोगों को संरक्षण और प्रेम दिया, उसी प्रकार उनका यह प्रतीकात्मक कंबल भी भक्तों को सुरक्षा और

अहमदाबाद, दि. 17-06-2026 बुधवार

इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी।’
सवाल हैं भी, तो उन्हें या तो आयोग और या फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। पर अब तो अदालती फैसलों पर भी संदेह पैदा किया जाता है। कहा जा रहा है कि आयोग को ‘एसआईआर’ कराने का अधिकार है ही नहीं। फिर मतदाता सूची में संशोधन या सुधार कैसे होगा? सोशल मीडिया के शोर ने स्थितियों को और बिगाड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 27 मई को याचिकाकर्ताओं के ज्यादातर तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। वहीं चुनाव-आयोग के तर्कों को स्वीकार किया और उन्हें और स्पष्ट किया। हालांकि यह मामला बिहार में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नियम को लागू करने से संबंधित था, लेकिन अदालत में विचारार्थ रखे गए मुद्दे और उसके निष्कर्ष देश भर की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। यह बात भी निर्विवाद है कि जिस मतदाता सूची पर चुनाव आधारित हैं, वह सटीक और विश्वसनीय होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल ने, इन सिद्धांतों या मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाया है। इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि आयोग की भारत के लोकतांत्रिक विकास में अग्रणी भूमिका है। और यह भी कि बड़े पैमाने पर प्रवासन, तीव्र शहरीकरण, अवैध सीमा पार आवागमन, मृत्यु की सूचना न देने और प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति को देखते हुए मतदाता सूची की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। कमजोर मतदाताओं पर सचूत का बोझ डालना, एक बौद्धिक दस्तावेज-प्रणाली, सुविधाएं कट जाएंगी।

US-Iran Deal से इजरायल बाहर! क्या समझौते का होगा पालन, ट्रंप vs नेतन्याहू अब होने वाला है?

अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर समझौता हो गया है। लेकिन इस समझौते ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू को मुश्किलों में ला खड़ा कर दिया है। वजह ये है कि जिस जंग में इजरायल सबसे आगे था। उसी जंग को खत्म करने वाले समझौते की शर्तें उसे अभी तक ठीक से पता भी नहीं हैं। 15 जून की शाम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर सहमति बन चुकी थी। समझौते पर डिजीटली साइन हो चुका है और 19 जून को स्थजरलैड में इसकी औपचारिक साईनिंग होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने समझौते के बारे में पूछा तो नेतन्याहू ने माना की इजरायल को अभी तक नहीं पता है कि इस डील में लिखा क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही है, उससे इजरायल लाभग बाहर ही रहा है। इसके बावजूद नेतन्याहू ने इस छह हफ्ते तक चले इस इरान अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियान को बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि इजरायल को एक न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान के खतरे से बच लिया। नेतन्याहू ने कहा कि समझौता हो या न हो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। न आज न कल, जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। यही मेरे जीवन का मिशन है। दरअसल, जहां खलत होने के तरीखों को लेकर नेतन्याहू को अपने देश के भीतर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उनकी अपनी सरकार के कुछ लोग भी सवाल उठा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल पर जंग खतरे का दबाव बनाया है और कई कैंची धाम केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आशा और विश्वास का केंद्र बन चुका है। यहां आने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, देश या संस्कृति से जुड़ा हो, उसे एक ही संदेश मिलता है—प्रेम, सेवा और ईश्वर स्मरण। यही बाबा नीम करौली की सबसे बड़ी शिक्षा थी और यही इस धाम की आत्मा भी है। हिमालय की शांत वादियों में स्थित यह पवन धाम आज भी उसी दिव्यता के साथ भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो समय उठर गया हो और मन सोचे ईश्वर की शरण में पहुंच गया हो। बाबा नीम करौली की कृपा, हनुमान जी की भक्ति और प्रकृति की अलौकिक छटा से आलोकित कैंची धाम वास्तव में उन विरले तीर्थों में से एक है, जहां श्रद्धा केवल दिव्यता नहीं देती, बल्कि हर श्वास में महसूस होती है।

समय-सीमा का कम होना और अपील प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित न करना सबसे ज्यादा चिंता के विषय हैं। अदालत के फैसले के बाद आयोग को असीमित प्रक्रियात्मक छूट मिल गई है। खासतौर से नागरिकता के मुद्दे पर भी, आयोग को मिली छूट को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है। मतदाता सूची के पहले से देश में नागरिकता को लेकर बहस चल रही है। हालांकि, एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके माफत ‘नागरिकता की सीमित जांच’ का आधार बना सकता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से एक वर्ग के मन में संशय हैं। खबरें हैं कि बिहार और बंगाल की नई सरकारों ने घोषणा की है कि मतदाता सूची से जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। अब मई के अंत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों (डेमोग्राफिक चेंज) का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले के प्राचीर से ‘घुसपैठियों’ का उल्लेख करते हुए ऐसी समिति की आवश्यकता की घोषणा की थी।

ऐसे समय में जब ‘घुसपैठिया’ शब्द को लेकर भय का माहौल है, तब आम नागरिक के मन में चिंता के कारण बनते हैं। करीब-करीब ऐसा ही भय देशभर में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के मन में है। बहुत से नहीं जानते कि उनके गृह-राज्य की सूची में उनका नाम है या नहीं। हाल में बंगाल में हुए चुनाव के समय प्रवासियों के बीच मची भागदड़ के पीछे एक भय यह भी था कि वोट नहीं डालेंगे, तो सुविधाएं कट जाएंगी।

कि इसाइल की उत्तरी सीमा की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, ‘हमने देखा कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। इसाइल अब वही गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता कि कोई भी हमारे नागरिकों की हत्या करे, उन्हें अपरा करने की कोशिश करे। हमारी सीमाओं पर कोई भी आतंकवादी संघटन मौजूद नहीं है। 15 जून को किसी सुुह हमला कर दे और लोगों की हत्या या अपहरण कर ले। ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा।’

स्टीनबर्ग के अनुसार, इसाइल का मुख्य लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र में शांति बहाल करना और हिज्बुल्लाह से पैदा होने वाले खतरे को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सुरक्षा खतरा सामने आता है तो इसाइल कार्रवाई करेगा, भले ही अमेरिका उससे सहमत न हो। इजराइल ईरान की बढ़ती ताकत को कुचलाता चाहता है। लेबनान में ईरान समर्थक हिज्बुल्ला और यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले कर डील में बाधा पैदा करेगा। ईरान ने परमाणु मुरे पर लिफलाह अपने 460 किलो परिष्कृत यूरेनियम को सौंपने का ऐलान नहीं किया है। ईरान ओमान को साथ लेकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस टैक्स लेने पर अड़ा हुआ है। जबकि अमेरिका यहां पर टैक्स वसूल के विरुद्ध है। अमेरिका को खाड़ी के देश ईरान के पुर्ननिर्माण के लिए 28 लाख करोड़ के पैकेज पर आसानी से राजी नहीं होंगे। सकुदी अरब और यूईई विरोध करेगे।

भारत की 55% तेल और 90% एलपीजी खलत होने के तरीखों को लेकर नेतन्याहू को अपने देश के भीतर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उनकी अपनी सरकार के कुछ लोग भी सवाल उठा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल पर जंग खतरे का दबाव बनाया है और कई कैंची धाम केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आशा और विश्वास का केंद्र बन चुका है। यहां आने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, देश या संस्कृति से जुड़ा हो, उसे एक ही संदेश मिलता है—प्रेम, सेवा और ईश्वर स्मरण। यही बाबा नीम करौली की सबसे बड़ी शिक्षा थी और यही इस धाम की आत्मा भी है। हिमालय की शांत वादियों में स्थित यह पवन धाम आज भी उसी दिव्यता के साथ भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो समय उठर गया हो और मन सोचे ईश्वर की शरण में पहुंच गया हो। बाबा नीम करौली की कृपा, हनुमान जी की भक्ति और प्रकृति की अलौकिक छटा से आलोकित कैंची धाम वास्तव में उन विरले तीर्थों में से एक है, जहां श्रद्धा केवल दिव्यता नहीं देती, बल्कि हर श्वास में महसूस होती है।

